(ख) ग्राम चाम आंशिक रूप से जलमग्न क्षेत्र में आता है और सड़क के साथ लगी कुछ दुकाने जल मग्नता के अर्न्तगत आ सकती है। मौजूदा पुनर्वास पैकेज के अनुसार भूमि और मौजूदा ढांचों के लिए मुआवजे की राशि देय है। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर आंशिक रूप से जलमग्न क्षेत्रों के ग्राम दुकान मालिकों को रिंग रोड के निकट लागत पर दुकान भूखण्ड दिया जाएगा। टिहरी जल विद्युत विकास निगम को तदनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(ग) ग्राम क्षेत्र में सभी प्रभावित भू-स्वामियों का पुनर्वास 2002 तक भूमि जब्त किए जाने से पूर्व देहरादून और हरिद्वार जिले में किए जाने की संभावना है।

(घ) जलमग्नता के कारणवश 4909 ग्रामीण परिवार पूर्णत प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 3998 परिवार आंशिक रूप से प्रभावित हैं जिन्हें पुनर्वासित नहीं किया जाना है। तथापि इन परिवारों को जलमग्नता के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए रोकड़ मुआवजा दिया जाना है।

Availability and Demand of Power

898. SHRI NARESH YADAV: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what was the overall availability and demand of power State-wise, during 1997-98 and 1998-99 and as on date;

(b) whether there was a shortfall of more than 20 per cent in demand during the same period which is expected to go up in the coming years;

(c) whether there was any proposal under Government's consideration for power production in the public sector to meet this shortage;

(d) if so, whether any decision has been taken in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) The details of energy requirement, availability and shortage in various States during 1997-98 and 1998-99 (April 1998 to Jan. 1999) are given at the Annexure. [*see Appendix 186, Annexue No. 19*]

(c) to (e) Power is being generated by Central public sector undertakings as well as state utilities and in the private sector. Decision on setting up new projects in the central sector and state sector are taken from time to time in keeping with the annual plan proposals.

बिजली की खपत का आकलन

899. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा घरेलू उपयोग और सरकारी संस्थाओं में बिजली की होने वाली खपत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल वार्षिक विद्युत खपत में इन क्षेत्रों का प्रतिशत कितना रहेगा और इन क्षेत्रों से आने वाली मांग के संबंध में आकलन किया है; और;

(ग) आगामी दशक में बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के लिए सरकार की कार्य-योजना क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) जी, हां। 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा घरेलू क्षेत्रों में सम्भावित खपत का आकंलन किया गया है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग और कुल खपत में विद्युत खपत का प्रतिशत, जैसा कि 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमानित किया गया है नीचे दिया गया है।

मि०यू० में ऊर्जा की मांग
(कुल उर्जा खपत में %)

श्रेणी	1997-98	1998-99 अनुमानित	1999-2000	2000-01	2001-02
कृषि	89418 (26.13)	94369 (25.61)	99325 (25.14)	104238 (24.70)	108249 (24.10)
उद्योग	136917 (40.01)	147123 (39.93)	156575 (39.64)	165837 (39.30)	175093 (39.00)
वाणिज्यिक	23829 (6.96)	25577 (6.94)	27442 (6.95)	29433 (6.98)	31559 (7.03)
विविध घरेलू	70555 (20.61)	78210 (21.22)	86559 (21.91)	95662 (22.67)	105586 (23.52)
कुल (अन्य को मिलाकर)	342253 (100.00)	368507 (100.00)	395042 (100.00)	421953 (100.00)	448996 (100.00)

(ग) नौवीं योजना के प्रारूप में योजना आयोग ने 40245 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की परिकल्पना की है। उपरोक्त के अतिरिक्त बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) विद्यमान सुविधाओं से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना।

(ii) निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सुधार कार्य आरम्भ करना।

(iii) मांग पक्ष प्रबन्धन और ऊर्जा संरक्षण।

(iv) अन्तर्राज्यीय/अन्तक्षेत्रीय आदान प्रदान को प्रोत्साहन।

(v) पारेषण और वितरण हानियों में कमी।

बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में धोखाधड़ी

900. **श्री एस०एम० कृष्णा:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 2 फरवरी, 1999 के द हिन्दुस्तान टाइम्स में "मैसिव रैकेट डिटेक्टेड इन बिहारस पावर्टी एलीविएसन प्रोग्राम्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) उनके मंत्रालय में ऐसे कार्यक्रमों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है और ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के वितरण के संबंध में राज्य की मशीनरी और उत्तरदायी बैंकों को किस प्रकार शामिल किया जाता है; और

(ग) क्या हाल में उनके मंत्रालय ने कर्नाटक के ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की है, यदि हां, तो अब तक किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौडा पाटील): (क) ऐसा कोई समाचार दिनांक 2 फरवरी, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में नहीं छपा। तथापि प्रश्न में बताया गया समाचार 12.2.1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की पूर्ण, निष्पक्ष और विस्तृत जांच करें तथा संघ सरकार को रिपोर्ट भेजें।

(ख) सावधिक प्रगति रिपोर्टों/विवरणियों; राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्रीय निरीक्षणों;